

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नागपुर-1

बनाम

मैसर्स इंडोरामा सिंथेटिक्स (I) लिमिटेड

(सिविल अपील क्रमांक 1834/2006)

25 अगस्त 2015

[ए.के. सीकरी और आर. एफ. नरीमन, जे.जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944: धारा 4 - लेन-देन मूल्य - अग्रिम लाइसेंस धारकों को निर्यात समझे जाने वाले माल को उन अन्य खरीदारों से ली जाने वाली कीमत से कम कीमत पर मंजूरी दी गई, जिनके पास अग्रिम लाइसेंस नहीं था - अतिरिक्त, खरीदारों द्वारा अग्रिम लाइसेंस के समर्पण पर निर्धारिती द्वारा प्राप्त प्रतिफल - लेनदेन मूल्य में शामिल करना - धारित: माल के लिए भुगतान की जा रही कीमत के अलावा, अतिरिक्त मौद्रिक प्रतिफल, यानी खरीदार द्वारा विक्रेता के पक्ष में अग्रिम आयात लाइसेंस का हस्तांतरण, माल के विक्रेता को कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात को प्रभावित करने और उत्पादन/खरीद की लागत को कम करने में सक्षम बनाना, एक विचार है, जिसके मौद्रिक मूल्य को नियमों के प्रावधानों के तहत लेनदेन मूल्य में शामिल किया जाना है, अर्थात् नियम 6- केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की कीमत का निर्धारण) नियम, 2000 - आर.6।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. जैसा कि धारा 4 को पढ़ने से स्पष्ट है, उत्पाद शुल्क ऐसी वस्तुओं के मूल्य के संदर्भ में उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर लगाया जाता है। आम तौर पर, सामान की कीमत, यानी वह कीमत जिस पर आम तौर पर निर्धारिती द्वारा खरीदार को ऐसा

सामान बेचा जाता है, सामान का मूल्य होता है। इस मूल्य को 'लेन-देन मूल्य' कहा जाता है। नियमों का नियम 6 निर्दिष्ट करता है कि यदि माल धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ए) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में बेचा जाता है, तो ऐसे माल का मूल्य ऐसे लेनदेन मूल्य का योग और 'खरीदार से निर्धारिती तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रवाहित होने वाले किसी भी अतिरिक्त विचार के धन मूल्य की राशि' माना जाएगा। इस नियम का निहितार्थ यह है कि किसी भी प्रकार का अतिरिक्त प्रतिफल जो खरीदार से निर्धारिती तक प्रवाहित होता है, उसके मौद्रिक मूल्य को लेनदेन मूल्य पर पहुंचने के दौरान शामिल किया जाना है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा अतिरिक्त प्रतिफल प्रत्यक्ष रूप से प्रवाहित हो और यहां तक कि अप्रत्यक्ष प्रतिफल भी सम्मिलित है। [पैरा 9, 1 ओ] [522-डी-जी; 524-बी-सी]

2. वर्तमान मामले में, खरीदार द्वारा अग्रिम लाइसेंस के आत्मसमर्पण के परिणामस्वरूप निर्धारिती को मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस जारी करने की सुविधा प्रदान की गई थी। इस प्रकार, खरीदार के पक्ष में वस्तुओं के सीधे आयात के लिए लाइसेंस को अमान्य किया जाना निर्धारिती के पक्ष में मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस जारी करने का ट्रिगर बिंदु था। निर्धारिती को लाइसेंस मिल गया और यह केवल खरीदारों द्वारा किए गए बलिदान के कारण संभव हो सका। इसके अलावा, खरीदारों ने अपने पक्ष में प्रत्यक्ष आयात के लिए अपने अग्रिम लाइसेंस को अमान्य कर दिया, जिसका एकमात्र उद्देश्य निर्धारिती से कम कीमत पर, यानी 37.50 रुपये प्रति किलोग्राम पर पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर खरीदना था। इसलिए, निर्धारिती का यह तर्क कि शुल्क के भुगतान के बिना आयात के रूप में लाभ निर्धारिती को केवल डीजीएफटी द्वारा जारी किए गए लाइसेंस के आधार पर प्राप्त होता है और डीजीएफटी से ग्राहक द्वारा प्राप्त अमान्य पत्र से प्राप्त नहीं होता है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। . [पैरा 12] 525-बी-ई]

आईएफजीएल रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, भुवनेश्वर-  
112001 (134) ईएलटी 230 - पर भरोसा किया गया।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बेंगलोर बनाम मझगांव डॉक लिमिटेड 2005 (187)  
ईएलटी 3 (एससी): 2005 (127) ईसीआर 268 (एससी) - अनुपयुक्त ठहराया गया।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, भुवनेश्वर- ॥ बनाम आईएफजीएल रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड  
2005 (2) सप्ल। एससीआर 480: (2005) 6 एससीसी 713; थॉमस बनाम थॉमस  
(1842) 2 क्यूबी 851; रे सोम्स (1897) 13 टीएलआर 439 - संदर्भित।

### केस कानून संदर्भ

2001 (134) ईएलटी 230 पैरा 2 पर निर्भर था

2005 (2) सप्ल.एससीआर 480 पैरा 3, 15 को संदर्भित करता है

(1842) 2 क्यूबी 851 पैरा 15 को संदर्भित करता है

(1897) 13 टीएलआर 439 पैरा 16 को संदर्भित करता है

2005 (127) ईसीआर 268 (एससी) को अनुपयुक्त पैरा 21,22 माना गया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1834/2006

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई की पश्चिमी  
क्षेत्रीय पीठ के दिनांक 12.07.2005 के निर्णय और आदेश से जो कि अपील संख्या  
ई/1318/04 में अंतिम आदेश संख्या ए/1417 /डब्ल्यूजेडबी/2005/आईएल के रूप में  
पारित किया गया।

अपीलकर्ता के लिए ए.के. पांडा, टी.सी.शर्मा, बिपिन बी. सिंह, बी. कृष्णा प्रसाद।

वी. लक्ष्मीकुमारन, एम.पी.देवनाथ, विवेक शर्मा, एल. चरणया, आदित्य  
भट्टाचार्य, आर. रामचन्द्रन, हेमन्त बजाज, आनंद के., प्रवीण कुमार प्रतिवादी।

न्यायालय का फैसला न्यायाधीश ए.के.सीकरी द्वारा सुनाया गया।

1. प्रतिवादी (बाद में 'निर्धारिती' के रूप में संदर्भित) पॉलिएस्टर चिप्स, पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर, पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न और अन्य सामान के निर्माण में लगा हुआ है। यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान पर इसे मंजूरी दे रहा था। इस अपील में शामिल अवधि 1999-2002 है। इस अवधि के दौरान, जिन सामानों को अग्रिम लाइसेंस धारकों को 'मानित निर्यात' के रूप में मंजूरी दी गई थी, उनकी कीमत उन अन्य खरीदारों से कम कीमत पर ली गई थी, जिनके पास अग्रिम लाइसेंस नहीं था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नागपुर-1 (बाद में 'राजस्व' के रूप में संदर्भित) के अनुसार, यह पाया गया कि उपरोक्त विशेष वर्ग के खरीदारों को कम कीमत पर सामान बेचने का कारण यह था कि निर्धारिती को 'अतिरिक्त प्रतिफल' प्राप्त हुआ था और इसलिए, वैधानिक योजना में निहित 'लेन-देन मूल्य' पर पहुंचने के लिए प्रदान किए गए फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए इसे शामिल करना आवश्यक था।

2. हम कथित 'अतिरिक्त विचार' का विवरण बाद में उचित चरण में सुनाएंगे। हालाँकि, हम यहां बता सकते हैं कि उपरोक्त खरीदारों के साथ अग्रिम लाइसेंस सरेंडर करने पर, निर्धारिती को निर्यात-आयात (EXIM) नीति के अनुसार सरकार/विदेश व्यापार महानिदेशक (DGFT) से वापसी प्राप्त हो सकती है और इसे अतिरिक्त विचारणीय बताया गया। इस समय यह बताना पर्याप्त होगा कि राजस्व ने पांच अलग-अलग कारण बताओ नोटिस जारी किए, जिसमें निर्धारिती को अंतर शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा गया, चूंकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 के संदर्भ में उक्त माल के 'लेन-देन मूल्य' पर पहुंचने के दौरान उक्त अतिरिक्त विचार को शामिल किया जाना था। (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की कीमत का निर्धारण) नियम, 2000 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 6 के साथ पढ़ें। निर्धारिती ने जवाब दाखिल कर

राजस्व के रुख को चुनौती दी। मामले की जांच करने के बाद, आयुक्त ने यह विचार किया कि कीमत खरीदार से निर्धारिती तक आने वाला एकमात्र विचार नहीं था। न केवल ऐसे खरीदार, जिन्हें कम कीमत पर सामान बेचा गया था, वे 'संबंधित व्यक्ति' थे, यहां तक कि सामान भी कम कीमत पर बेचे गए थे। इसलिए, आयुक्त ने कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित अंतर शुल्क की मांग की पुष्टि की और जुर्माना और ब्याज भी लगाया। निर्धारिती ने सीमा शुल्क उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में, न्यायाधिकरण) के समक्ष अपील दायर करके आयुक्त के आदेश को चुनौती दी कि अधिनियम की धारा 4 के तहत 'अतिरिक्त प्रतिफल' केवल खरीदार से निर्धारिती तक आने वाले अतिरिक्त प्रतिफल को संदर्भित करता है और वर्तमान मामले में 'डीम्ड एक्सपोर्ट' के अग्रिम लाइसेंस खरीदारों से ऐसा कोई अतिरिक्त प्रतिफल नहीं मिला है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में ट्रिब्यूनल ने आईएफजीएल रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, भुवनेश्वर- II के मामले में अपने स्वयं के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा अनुमत वैधानिक लाभों को खरीदार से निर्माता को मिलने वाले अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में नहीं माना जा सकता है। ट्रिब्यूनल की राय में, ड्रॉबैक सरकार से प्राप्त हुआ था, न कि खरीदारों से और, इसलिए, इस तरह की कमी को अधिनियम की धारा 4 के तहत परिभाषा के अनुसार 'लेनदेन मूल्य' पर पहुंचने के उद्देश्य से अतिरिक्त विचार के रूप में नहीं माना जा सकता है।

3. प्रासंगिक रूप से, आईएफजीएल के मामले में ट्रिब्यूनल के फैसले को इस न्यायालय ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, भुवनेश्वर- II बनाम आईएफजीएल रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड 2 में खारिज कर दिया है। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने इस तरह के विचार, अर्थात् शुल्क वापसी पर विचार किया है। , 'अतिरिक्त विचार' के रूप में विक्रेता को मिलने वाले शुल्क वापसी का लाभ खरीदारों द्वारा अग्रिम लाइसेंस के आत्मसमर्पण

का परिणाम था। उपरोक्त राय बनाने में होने वाली चर्चा और तर्क निर्णय के पैरा 9 में निहित है, जो इस प्रकार है:

"9. अंततः इस बात पर सहमति हुई कि एम.एस. विशाखापत्तनम अपने अग्रिम लाइसेंस सरेंडर कर देगा और इसके बदले में उत्तरदाताओं को अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस मिलेंगे। इस प्रकार, मेसर्स विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के अग्रिम लाइसेंस के बिना, उत्तरदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। कीमतें वैसी ही होंगी जैसी पहले बताई गई थीं। यह केवल मेसर्स विशाखापत्तनम स्टील प्लांट द्वारा अग्रिम लाइसेंस सरेंडर किए जाने और उसके बदले में उत्तरदाताओं को उपलब्ध कराए जाने वाले अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस के कारण है, जिससे उत्तरदाता कम कीमतों की पेशकश कर सके। मेसर्स विशाखापत्तनम स्टील प्लांट द्वारा लाइसेंस सरेंडर करने और उसके परिणामस्वरूप उत्तरदाताओं को लाइसेंस मिलने का किसी भी आयात और निर्यात नीति से कोई लेना-देना नहीं है। यह सीधे तौर पर दो पक्षों के बीच अनुबंध का मामला था। इसके परिणामस्वरूप मेसर्स विशाखापत्तनम स्टील प्लांट से उत्तरदाताओं को मिलने वाले "एडवांस इंटरमीडिएट लाइसेंस" के माध्यम से अतिरिक्त विचार किया गया। वहां से प्राप्त मूल्य कीमत में शामिल है। ट्रिब्यूनल का यह कहना गलत था कि ऐसी व्यवस्था को कभी भी अतिरिक्त विचार के मंच पर नहीं रखा जा सकता। ऐसा कहते हुए ट्रिब्यूनल ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है और/या उसे नजरअंदाज कर दिया है कि यह उत्तरदाताओं और मेसर्स विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के बीच बिक्री के अनुबंध के अनुसरण में था कि लाइसेंस उत्तरदाताओं को उपलब्ध कराए गए थे। निर्यात और आयात नीति का उस व्यवस्था/अनुबंध से कोई लेना-देना नहीं था जिसके तहत लाइसेंस खरीदार

से विक्रेता तक आते थे। दोहराव की कीमत पर यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि यदि उत्तरदाताओं के पास स्वयं अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस था यानी अनुबंध के प्रयोजनों के लिए मेसर्स विशाखापत्तनम स्टील प्लांट को अपने लाइसेंस सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं थी, तो ट्रिब्यूनल का तर्क सही हो सकता था . लेकिन यहां, बिक्री के अनुबंध के अनुसरण में, खरीदार से विक्रेता तक सीधे अतिरिक्त प्रतिफल का प्रवाह होता है। उसका मूल्य कीमत में जोड़ा जाना चाहिए। इस प्रकार हम इस व्यापक दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि जहां पार्टियां सरकार की नीतियों और उससे मिलने वाले लाभों का लाभ उठाती हैं, तो ऐसे लाभ को "अतिरिक्त विचार" नहीं कहा जा सकता है।"

4. इस तरह के मामले में, यह न्यायालय उपरोक्त निर्णय का पालन कर सकता है और इस अपील की अनुमति देते हुए ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर सकता है। हालाँकि, निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री वी. लक्ष्मीकुमारन ने जोरदार और भावुक दलील दी कि /एफजीएल के 3 मामले में इस न्यायालय के उपरोक्त फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है। इस प्रकार, उन्होंने मामले को एक बड़ी पीठ को सौंपने का अनुरोध किया। इस दिशा में विस्तृत और विस्तृत प्रस्तुतियाँ की गईं जिनका राजस्व के विद्वान वकील ने दृढ़ता से खंडन किया। हम तुरंत रिकॉर्ड कर सकते हैं कि निर्धारिती का वकील हमें मामले को बड़ी बेंच में भेजने के लिए मनाने में सफल नहीं हुआ है। इसके बाद, हम इस दृष्टिकोण को अपनाने के अपने कारणों को दर्ज करेंगे। इस प्रयोजन के लिए, हम सबसे पहले इस स्तर पर उस तंत्र के बारे में बता सकते हैं जो निर्धारिती की किटी में शुल्क वापसी का लाभ प्राप्त करने में जाता है।

5. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निर्धारिती अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने के अलावा, घरेलू खरीदारों के दो वर्गों को पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर बेच रहा था।

घरेलू खरीदारों की एक श्रेणी वे थे जिनके पास अग्रिम लाइसेंस था और दूसरी श्रेणी बिना किसी लाइसेंस के थी। निर्धारिती ने दो अलग-अलग मूल्य सूचियां जारी की थीं। वे खरीदार जिनके पास अग्रिम लाइसेंस था लेकिन वे उक्त लाइसेंस सरेंडर करने के लिए सहमत थे, उन्हें 37.50 प्रति किलोग्राम की कीमत की पेशकश की गई थी। अन्य श्रेणी, जिनके पास ऐसा कोई लाइसेंस नहीं था, को 1.50 प्रति किलोग्राम की दर से माल बेचा गया। निर्धारिती के अनुसार, यह प्रासंगिक अवधि के दौरान निर्यात के लिए अपने स्वयं के अग्रिम लाइसेंस के मुकाबले 36 रुपये प्रति किलोग्राम की औसत कीमत पर पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर का निर्यात कर रहा था।

6. एडवांस लाइसेंस EXIM पॉलिसी के तहत जारी किया जाता है। अग्रिम लाइसेंस धारक तैयार माल के निर्माण के लिए उक्त लाइसेंस के विरुद्ध आयातित कच्चा माल खरीद सकता है। हालाँकि, EXIM नीति 1997-2002 के पैरा 7.7 के अनुसार, सीधे आयात के बदले स्वदेशी स्रोत से सामग्री प्राप्त करने का इरादा रखने वाले अग्रिम लाइसेंस धारक के पास विदेशी मुद्रा / भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित अग्रिम रिलीज ऑर्डर के विरुद्ध उन्हें प्राप्त करने का विकल्प था। . ऐसे मामले में, सीधे आयात के लिए लाइसेंस को अमान्य कर दिया जाना था और एआरओ के रूप में अनुमति जारी की जानी थी, जिससे माल के आपूर्तिकर्ता को डीमड निर्यात का लाभ मिल सके। EXIM नीति के पैरा 10.2 में आपूर्ति की श्रेणियां निर्धारित की गई हैं जिन्हें नीति के तहत 'मानित निर्यात' के रूप में दर्ज किया जाएगा। ऐसा पहला खंड (ए) 'शुल्क छूट माफी योजना के तहत अग्रिम लाइसेंस/आरसी के खिलाफ माल की आपूर्ति' था। पैरा 10.3 के तहत, डीमड निर्यात के लिए लाभ निर्दिष्ट किए गए थे। मध्यवर्ती आपूर्ति/डीमड निर्यात के लिए अग्रिम लाइसेंस को डीमड निर्यात के लाभों में से एक के रूप में निर्दिष्ट किया गया था।



7. अग्रिम लाइसेंस धारक श्रेणी के खरीदारों ने अपने लाइसेंस अमान्य/सरेंडर करवा दिए। इसके बाद, डीजीएफटी ने निर्धारिती के पक्ष में लाइसेंस जारी किया, जिसमें उसे स्वदेशी निर्माताओं से शुल्क मुक्त सामान खरीदने और ऐसे खरीदारों को इस सामग्री की आपूर्ति करने की अनुमति दी गई, इसे 'मानित निर्यात' माना गया, जिससे शुल्क वापसी का लाभ प्राप्त हुआ। EXIM नीति के पैरा 7.11 ने इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया और यह इस प्रकार है:

"7.11 मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस - मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस पर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस मध्यवर्ती विनिर्माण द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के सीधे आयात के लिए लाइसेंस को अमान्य करने के बाद जारी किया जाएगा। ऐसे मामलों में, अमान्यकरण पत्र की एक प्रति लाइसेंस धारक को दी जाएगी और उसकी प्रति मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता के साथ-साथ मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता के लाइसेंसिंग प्राधिकारी के साथ-साथ मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता के लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी। ऐसे मामले में लाइसेंसधारी के पास या तो भौतिक निर्यात/मानित निर्यात के लिए अग्रिम लाइसेंस धारक को मध्यवर्ती उत्पाद की आपूर्ति करने या सीधे निर्यात करने का विकल्प होता है।"

8. उपरोक्त आख्यानों से पता चलता है कि निर्धारिती को शुल्क वापसी मिल सकती है और ऐसा तब हो सकता है जब अग्रिम लाइसेंस धारक श्रेणी के खरीदारों ने अपने अग्रिम लाइसेंस को अमान्य कर दिया हो, जिससे ऐसे अग्रिम लाइसेंस के तहत अर्जित लाभ सरेंडर हो गए हों। विचार के लिए मुद्दा यह है कि क्या यह नियमों के नियम 6 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 4 में निहित 'लेन-देन मूल्य' की परिभाषा के अनुसार निर्धारिती द्वारा प्राप्त 'अतिरिक्त विचार' का गठन करेगा। इसलिए,

हम धारा 4 के प्रावधानों के प्रासंगिक हिस्से को पुनः प्रस्तुत करेंगे जो भौतिक समय पर मौजूद थे, जो इस प्रकार हैं:

"4. उत्पाद शुल्क वसूलने के प्रयोजनों के लिए उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्यांकन। - (1) जहां इस अधिनियम के तहत, किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर उनके मूल्य के संदर्भ में उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, तो, माल के प्रत्येक निष्कासन पर , ऐसा मूल्य होगा-

(ए) ऐसे मामले में जहां सामान निर्धारिती द्वारा निष्कासन के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए बेचा जाता है, निर्धारिती और माल का खरीदार संबंधित नहीं हैं और कीमत बिक्री के लिए एकमात्र विचार है, लेनदेन मूल्य हो।

XX

XX

XX

XX

(डी) "लेन-देन मूल्य" का मतलब माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत है, जब बेचा जाता है, और कीमत के रूप में ली गई राशि के अलावा, कोई भी राशि जो खरीदार निर्धारिती को या उसकी ओर से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है , बिक्री के कारण या उसके संबंध में, चाहे बिक्री के समय या किसी अन्य समय पर देय हो, जिसमें शामिल है, लेकिन यह विज्ञापन या प्रचार, विपणन और बिक्री संगठन के खर्चों, भंडारण, बाहरी हैंडलिंग, सर्विसिंग, वारंटी, कमीशन या किसी अन्य मामले के लिए ली गई या प्रावधान करने के लिए ली गई किसी भी राशि तक सीमित नहीं है; लेकिन इसमें ऐसी वस्तुओं पर वास्तव में भुगतान की गई या वास्तव में देय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों की राशि, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।"

9. जैसा कि उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से स्पष्ट है, उत्पाद शुल्क ऐसी वस्तुओं के मूल्य के संदर्भ में उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर लगाया जाता है। आम तौर पर, सामान की कीमत, यानी वह कीमत जिस पर आम तौर पर निर्धारिती द्वारा किसी खरीदार को ऐसा सामान बेचा जाता है, वह सामान का मूल्य होता है। इस मूल्य को 'लेन-देन मूल्य' कहा जाता है। केंद्र सरकार ने ऐसे नियम भी बनाए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ मूल्य के निर्धारण के लिए प्रावधान निर्धारित करते हैं। इसका नियम 6, जिससे हम विशेष रूप से चिंतित हैं, इस प्रकार है:

"नियम 6. जहां उत्पाद शुल्क योग्य सामान अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ए) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में बेचा जाता है, उन परिस्थितियों को छोड़कर जहां कीमत बिक्री के लिए एकमात्र विचार नहीं है, ऐसे माल का मूल्य ऐसे लेन-देन मूल्य और खरीदार से करदाता तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रवाहित होने वाले किसी भी अतिरिक्त विचार के धन मूल्य की राशि का योग माना जाएगा।

स्पष्टीकरण- शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, उचित रूप से विभाजित किया गया है,

चाहे ऐसी वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उपयोग के लिए खरीदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निःशुल्क या कम लागत पर आपूर्ति की गई हो, इस हद तक

इस तरह के मूल्य को वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत में शामिल नहीं किया गया है, इसे माल की बिक्री के संबंध में खरीदार से निर्धारिती

तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहने वाले अतिरिक्त विचार के धन मूल्य की राशि माना जाएगा और तदनुसार एकत्र किया जाएगा। अर्थात्:

(i) ऐसे माल से संबंधित सामग्रियों, घटकों, भागों और समान वस्तुओं का मूल्य;

(ii) ऐसे सामानों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, डाई, सांचे, चित्र, ब्लू प्रिंट, तकनीकी मानचित्र और चार्ट और इसी तरह की वस्तुओं का मूल्य;

(iii) ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में पैकेजिंग सामग्री सहित उपभोग की गई सामग्री का मूल्य;

(iv) उत्पादन के कारखाने के अलावा कहीं और किए गए इंजीनियरिंग, विकास, कला कार्य, डिजाइन कार्य और योजनाओं और रेखाचित्रों का मूल्य और ऐसे सामानों के उत्पादन के लिए आवश्यक।

10. यहां तक कि जब ये सामान निर्धारिती द्वारा अलग-अलग कीमतों पर खरीदारों के विभिन्न वर्गों (संबंधित व्यक्ति नहीं) को बेचे जाते हैं, तो ऐसी प्रत्येक कीमत को खरीदारों के प्रत्येक वर्ग के संबंध में ऐसे सामान की सामान्य कीमत माना जाएगा। हालाँकि, इसी खंड में निहित 'लेन-देन मूल्य' की परिभाषा के अनुसार, यानी धारा 4(3)(डी), कुछ विशेष परिस्थितियों में, उस कीमत पर कुछ शुल्क जोड़े जा सकते हैं जिस पर माल वास्तव में बेचा जाता है। इनमें विज्ञापन या प्रचार, विपणन और बिक्री संगठन के खर्च, भंडारण, बाहरी हैंडलिंग, सर्विसिंग, वारंटी, कमीशन आदि का प्रावधान शामिल है। वर्तमान मामले में, हम इस पहलू से चिंतित नहीं हैं। हालाँकि, नियमों का नियम 6 निर्दिष्ट करता है कि यदि सामान धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ए) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में बेचा जाता है, तो ऐसे माल का मूल्य ऐसे लेनदेन मूल्य

का योग और 'खरीदार से निर्धारिती तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रवाहित होने वाले किसी भी अतिरिक्त विचार के धन मूल्य की राशि' माना जाएगा। इस नियम का निहितार्थ यह है कि किसी भी प्रकार का अतिरिक्त प्रतिफल जो खरीदार से निर्धारिती तक प्रवाहित होता है, उसके मौद्रिक मूल्य को लेनदेन मूल्य पर पहुंचने के दौरान शामिल किया जाना है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा अतिरिक्त प्रतिफल प्रत्यक्ष रूप से प्रवाहित हो और यहां तक कि अप्रत्यक्ष प्रतिफल भी सम्मिलित है। इस संदर्भ में हमें यह जांचना होगा कि क्या शुल्क वापसी के रूप में प्रतिफल, जो निर्धारिती के पक्ष में अर्जित हुआ, खरीदार के साथ जुड़ा हो सकता है। इसे अन्यथा कहें तो, हालांकि शुल्क वापसी का तत्काल स्रोत सरकार है, क्या इसका प्रवाह खरीदार तक खोजा जा सकता है? यदि ऐसा है, तो यह खरीदार से आने वाली अप्रत्यक्ष स्वीकृति का मामला बन सकता है और इसे लेनदेन मूल्य में जोड़ा जा सकता है।

11. आईएफजीएल 4 के मामले में, इस न्यायालय ने उपरोक्त मुद्दे का सकारात्मक उत्तर दिया है। निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि उक्त निर्णय लगभग समान तथ्य स्थिति पर दिया गया था। इसीलिए श्री लक्ष्मीकुमारन का प्रयास हम पर एक अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए दबाव डालना है। उन्होंने यह तर्क देकर उक्त मामले में न्यायालय की राय को बदनाम करने की मांग की कि मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस डीजीएफटी द्वारा एक्विजम नीति के तहत निर्धारिती को दिया गया था और इसका खरीदार से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने माना कि ऐसा तभी हो सकता है जब खरीदारों के अग्रिम लाइसेंस अमान्य हो जाएं। लेकिन उनका स्पष्टीकरण यह था कि यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा लाइसेंस निर्धारिती को केवल इसलिए जारी किया जा सकता है क्योंकि खरीदार के पक्ष में अग्रिम लाइसेंस अमान्य हो गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डीजीएफटी

अभी भी निर्धारिती को मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस जारी करने से इनकार कर सकता है।

12. यह तर्क हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं करता है। तथ्य यह है कि निर्धारिती को मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस जारी करने की सुविधा खरीदार द्वारा या खरीदार के पक्ष में अग्रिम लाइसेंस के आत्मसमर्पण के परिणामस्वरूप की गई थी। इस प्रकार, खरीदार के पक्ष में वस्तुओं के सीधे आयात के लिए लाइसेंस को अमान्य किया जाना निर्धारिती के पक्ष में मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस जारी करने का ट्रिगर बिंदु था। डीजीएफटी की ओर से निर्धारिती के पक्ष में लाइसेंस जारी करने से इनकार करने की संभावना केवल अनुमान के दायरे में है। तथ्य यह है कि निर्धारिती को लाइसेंस मिल गया और यह खरीदारों द्वारा किए गए बलिदान के कारण ही संभव हो सका। इसके अलावा, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि खरीदारों ने अपने पक्ष में प्रत्यक्ष आयात के लिए अपने अग्रिम लाइसेंस को अमान्य कर दिया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य निर्धारिती से कम कीमत, यानी 37.50 प्रति किलोग्राम पर पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर खरीदना था। इसलिए, निर्धारिती का तर्क है कि शुल्क के भुगतान के बिना आयात के रूप में लाभ निर्धारिती को केवल डीजीएफटी द्वारा निर्धारिती को जारी किए गए लाइसेंस के आधार पर प्राप्त होता है और ग्राहक को डीजीएफटी से प्राप्त अमान्यकरण पत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह इतना सरल तर्क है कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

13. एक अन्य तर्क जो निर्धारिती के लिए विद्वान वकील द्वारा दिया गया था, वह यह था कि उत्पादन की लागत में परिणामी कमी के साथ वैधानिक अधिसूचना के कारण इनपुट पर सीमा शुल्क में बचत के कारण निर्धारिती द्वारा खरीददारों की अग्रिम लाइसेंस धारक श्रेणी से रियायती मूल्य वसूला जाता है। और, इसलिए, यह खरीदार से मिलने वाला प्रतिफल नहीं है। इस संबंध में, प्रस्तुतीकरण यह था कि पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के निर्माण में जाने वाले इनपुट पर अन्यथा लगाए जाने वाले सीमा शुल्क को

केंद्र सरकार द्वारा जारी वैधानिक अधिसूचना, अधिसूचना संख्या 31/1997-सीयूएस द्वारा छूट दी गई है, और यह इस अधिसूचना के तहत निर्धारिती द्वारा प्राप्त लाभ के कारण यह अग्रिम लाइसेंस रखने वाले अंतिम निर्यातक को रियायती मूल्य पर पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर की आपूर्ति को प्रभावित करने में सक्षम है। इसलिए, किसी ग्राहक, जो निर्यातक है, को दी जाने वाली अतिरिक्त छूट कभी भी अतिरिक्त विचार नहीं होती है।

14. निर्धारिती के लिए विद्वान वकील का उपरोक्त तर्क प्रभावशाली प्रतीत हो सकता है, जब अलगाव में लिया जाता है, अर्थात्, सभी उपस्थित तथ्यों पर ध्यान दिए बिना। हालाँकि, जब इस तर्क का परीक्षण संपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जैसा कि पहले ही ऊपर ध्यान दिया जा चुका है, तो इस तर्क का खोखलापन उजागर हो जाता है, क्योंकि यह तर्क उस मूलभूत तथ्य को खत्म कर देता है कि निर्धारिती अपने पक्ष में डीजीएफटी द्वारा जारी लाइसेंस के आधार पर अधिसूचना संख्या डी 31/1997-सीयूएस का लाभ प्राप्त करने में सक्षम था और डीजीएफटी द्वारा निर्धारिती को उक्त लाइसेंस जारी करने का कारण खरीदारों द्वारा अग्रिम लाइसेंस को अमान्य करना था। इसलिए, स्रोत या गंगोत्री जहां से लाभ अंततः निर्धारिती तक पहुंचा है वह अग्रिम लाइसेंस है जो खरीदारों के पास था और उनके अमान्यकरण के कार्य ने लाभ को प्रवाहित करना संभव बना दिया ताकि निर्धारिती की धारा तक पहुंच सके।

15. श्री लक्ष्मीकुमारन द्वारा उठाया गया एक और तर्क यह था कि खरीदारों की इस श्रेणी को तैयार किया जाए, अर्थात्, जो अग्रिम लाइसेंस के धारक हैं/थे, रियायती मूल्य पर खरीद के लिए पात्र होने के लिए निर्धारिती द्वारा केवल 'माल की बिक्री की शर्त' रखी गई थी। उन्होंने कहा कि 'यह माल की बिक्री पर विचार नहीं किया गया था।' इस प्रकार, उन्होंने बिक्री की शर्त और माल की बिक्री के प्रतिफल के बीच अंतर किया और इस प्रस्तुतिकरण के समर्थन में थॉमस बनाम थॉमस 5 में अंग्रेजी न्यायालय के प्रसिद्ध और क्लासिक फैसले का हवाला दिया। इस फैसले का विश्लेषण चिट्ठी ऑन

कॉन्ट्रैक्ट्स (31वां संस्करण - खंड I) द्वारा किया गया है और श्री लक्ष्मीकुमारन ने अपने प्रस्तुतिकरण के हिस्से के रूप में उक्त विश्लेषण किया है। यह एक ऐसा मामला था जहां एक वसीयतकर्ता ने, अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले, इच्छा व्यक्त की थी कि उसकी विधवा को, उसके जीवनकाल के दौरान, वह घर मिले जिसमें वह रहता था, या £100। उनकी मृत्यु के बाद, उनके निष्पादकों ने 'ऐसी इच्छा पर विचार करते हुए' विधवा को उसके जीवनकाल के दौरान या जब तक उसे एक खिड़की जारी रखनी चाहिए, घर देने का वादा किया, 'फिर भी बशर्ते और इसके द्वारा आगे सहमति व्यक्त की जाए' कि उसे ज़मीन के किराये के लिए प्रति वर्ष £1 का भुगतान करना चाहिए, और घर की मरम्मत करानी चाहिए। इस वादे के उल्लंघन के लिए विधवा द्वारा की गई कार्रवाई में, इसके लिए प्रतिफल को विधवा द्वारा भुगतान और मरम्मत करने का वादा बताया गया था। एक आपत्ति कि घोषणा में विचार के भाग का उल्लेख छोड़ दिया गया है, अर्थात् वसीयतकर्ता की इच्छा को अस्वीकार कर दिया गया। पैटसन, जे. ने कहा: 'उद्देश्य विचारशील के समान नहीं है। प्रतिफल का अर्थ कुछ ऐसा है जो वादी की ओर से कानून की नजर में मूल्यवान है।' उपरोक्त टिप्पणियों पर टिप्पणी करते हुए, चिट्टी कहते हैं:

"इस टिप्पणी को गलत नहीं समझा जाना चाहिए: वादा करने का एक सामान्य उद्देश्य प्रतिफल प्राप्त करने की इच्छा है; और वचनदाता की ओर से कोई कार्य या सहनशीलता (जब तक कि अदालत किसी प्रतिफल का "आविष्कार" करने के लिए तैयार न हो) प्रतिफल का गठन करने में असफल हो सकती है, क्योंकि इसे सुरक्षित करना वचनदाता का उद्देश्य नहीं था। पैटसन जे का मतलब यह था कि वादा करने का मकसद तब तक विचार करने लायक नहीं होता जब तक कि दो और आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जातीं, जैसे: (i) कि वादे के बदले में सुरक्षित की गई चीज़ "कानून की नजर में कुछ मूल्य की" थी; और (ii) यह वादी से



स्थानांतरित हो गया। विचार और उद्देश्य विपरीत नहीं हैं; पहली अवधारणा बाद वाली अवधारणा का एक उपखंड है। किसी वादे का प्रतिफल हमेशा वादा करने का एक उद्देश्य होता है (जब तक कि प्रतिफल नाममात्र का या आविष्कृत न हो); लेकिन वादा करने का मकसद कानून में उस पर विचार करना जरूरी नहीं है। इस प्रकार थॉमस बनाम थॉमस में वसीयतकर्ता की इच्छा निष्पादकों के वादे का एक मकसद थी लेकिन इसके लिए विचार का हिस्सा नहीं थी। विधवा का भुगतान और मरम्मत का वादा निष्पादकों के वादे का एक और मकसद था और उस वादे पर विचार किया गया।"

16. इसी निर्णय से चिट्ठी विचार और शर्त के बीच अंतर भी स्पष्ट करता है। उनके अनुसार, वादी का विधवा बने रहना विचार का हिस्सा नहीं था, बल्कि निष्पादक के वादे को लागू करने के उसके अधिकार की एक शर्त थी। यह मामला रे सोम्स 6 में एक अन्य फैसले के विपरीत है। इस संबंध में चर्चा इस प्रकार है:

"दूसरी ओर, रे सोम्स में ए ने बी को £3,000 देने का वादा किया था यदि बी एक स्कूल स्थापित करेगा जिसके संचालन में ए को सक्रिय भूमिका निभानी थी। यह माना गया कि, स्कूल की स्थापना करके, बी ने ए के वादे पर विचार किया था। ऐसा लगता है कि प्रतिफल और शर्त के बीच अंतर, ऐसे मामलों में, इस बात पर निर्भर करता है कि "एक उचित व्यक्ति यह समझेगा या नहीं समझेगा कि शर्त के प्रदर्शन को वादे के बदले कीमत या विनिमय के रूप में अनुरोध किया गया था।" थॉमस बनाम थॉमस में निष्पादकों ने वादी से विधवा बने रहने का अनुरोध नहीं किया था; जबकि रे सोम्स में ए का अनुरोध है कि बी को स्कूल स्थापित करना चाहिए, ए के प्रबंधन में भाग लेने के व्यक्त इरादे से अनुमान लगाया जा सकता है। इस अंतर को कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल

कंपनी द्वारा और अधिक स्पष्ट किया गया है, जहां दावेदार ने स्मोक-बॉल का उपयोग करके प्रतिवादी के वादे पर विचार किया; लेकिन उसे इन्फ्लूएंजा होना उस वादे को लागू करने के उसके अधिकार की एक शर्त थी।"

17. हमें डर है, प्रतिफल और शर्त के बीच ऐसा अंतर, जैसा कि निर्धारिती के लिए विद्वान वकील द्वारा मांगा गया है, तत्काल मामले पर लागू नहीं होगा। यह संभव था यदि खरीदारों और निर्धारिती के बीच लेनदेन को अलग-अलग देखा जाए। हालाँकि, वर्तमान मामले में, दोहराव की कीमत पर इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि खरीदार द्वारा अग्रिम लाइसेंस को अमान्य करने का परिणामी प्रभाव निर्धारिती के पक्ष में मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए लाइसेंस जारी करना था और उक्त लाइसेंस ने निर्धारिती के पक्ष में कुछ लाभ सुनिश्चित किए। वर्तमान मामले में, इन तथ्यों पर, हमें बस यह देखना होगा कि क्या 'लेन-देन मूल्य' की परिभाषा, जैसा कि नियमों के नियम 6 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 4 में निहित है, इस लाभ को अतिरिक्त विचार के रूप में शामिल करेगी। . हमारा निष्कर्ष यह है कि यह अप्रत्यक्ष रूप से खरीदारों से निर्धारिती तक प्रवाहित होने वाले अतिरिक्त प्रतिफल के दायरे में आएगा। इसलिए, तत्काल मामला रे सोम्स के फैसले के समान है।

18. इस स्तर पर, हम आयुक्त द्वारा निकाले गए निम्नलिखित निष्कर्षों को याद करना चाहेंगे, जो कि न्यायाधिकरण द्वारा लागू निर्णय में अप्रसन्न नहीं हैं या यहां तक कि निर्धारिती द्वारा विवादित भी नहीं हैं:

(ए) निर्धारिती ने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में सामान्य खरीदारों से ली गई कीमत की तुलना में बहुत कम कीमत पर एक विशेष प्रकार के खरीदारों को सामान की आपूर्ति की थी क्योंकि इसने ऐसे खरीदारों से अग्रिम लाइसेंस को अमान्य करने की

सुविधा प्राप्त कर ली थी और तैयार माल के निर्माण के लिए ऐसे लाइसेंस के खिलाफ आयातित कच्चे माल (शुल्क मुक्त) की खरीद की थी। इसलिए, यह आरोप लगाया गया है कि निर्धारिती और खरीदारों के बीच एक-दूसरे के व्यवसाय में पारस्परिक हित थे, अधिनियम की धारा 4(1)"(ए) के प्रावधानों के अनुसार इन मामलों में प्रवाह वापस आ गया था और कीमत बिक्री के लिए एकमात्र विचार नहीं थी।

(बी) इसलिए, वे अधिनियम की पूर्ववर्ती धारा 4(4){सी}, वर्तमान में धारा 4(3) (बी)(iv) के प्रावधानों के संदर्भ में संबंधित व्यक्ति थे।

(सी) यह देखा गया है कि अग्रिम रिलीज ऑर्डर पर एक्जिम नीति का पैरा 7.7 हितों की पारस्परिकता की बात करता है क्योंकि निर्धारिती ने कंसाइनी के अग्रिम लाइसेंस को अमान्य करने के खिलाफ शुल्क मुक्त आयातित कच्चे माल की खरीद की थी और बदले में इसने अन्य सामान्य खरीदारों की तुलना में तैयार माल उक्त खेपों को कम कीमतों पर बेचा। इस प्रकार, कीमत ही एकमात्र विचार नहीं थी।

(डी) एक बार जब अग्रिम लाइसेंस अमान्य हो जाता है, तो उन खरीदारों को उक्त निकासी, जिनके पास पहले उक्त लाइसेंस थे, को डीमड एक्सपोर्ट के रूप में नहीं माना जाएगा और निर्धारिती ने उत्पाद शुल्क के भुगतान पर ऐसे खरीदारों को उक्त सामान की मंजूरी दे दी है, लेकिन सामान्य खरीदारों को दी गई मंजूरी से कम मूल्य पर। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारिती ने इन लेनदेन में दोहरा लाभ प्राप्त किया है, यानी (i) बढ़ी हुई बिक्री और कम मूल्य पर कम शुल्क का भुगतान किया; और (ii) आयातित शुल्क मुक्त कच्चा माल।

(ई) इस मामले में, शुल्क मुक्त आयातित कच्चे माल की खरीद का अधिकार खरीदार द्वारा आपूर्तिकर्ता को हस्तांतरित किया जा रहा है। यह उक्त सामान के खरीदार

से विक्रेता, जो कि निर्धारित है, के पास अतिरिक्त प्रतिफल के प्रवाह को इंगित करता है।

19. इस मामले के तथ्यों पर, हमारी राय है कि आयुक्त इस तथ्य के संबंध में सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि माल के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत के अलावा अतिरिक्त मौद्रिक विचार, यानी खरीदार द्वारा विक्रेता के पक्ष में अग्रिम आयात लाइसेंस का हस्तांतरण, माल के विक्रेता को कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात को प्रभावित करने और उत्पादन/खरीद की लागत को कम करने में सक्षम बनाना, एक विचार है, जिसके मौद्रिक मूल्य पर नियमों के प्रावधानों, यानी नियम 6 के तहत विचार किया जाना है।

20. इस प्रकार, हमें होने वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से कोई कारण नहीं दिखता है।

21. इससे पहले कि हम अलग हों, एक और पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है जिस पर श्री लक्ष्मीकुमारन ने हमारा ध्यान आकर्षित किया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बेंगलूर बनाम मझगांव डॉक लिमिटेड 9 में इस न्यायालय के एक अन्य फैसले का हवाला देते हुए, यह दिखाने का व्यर्थ प्रयास किया गया कि यह निर्णय /एफजीएल के 10 मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विपरीत था। हमें ऐसा नहीं लगता। दिलचस्प बात यह है कि माननीय न्यायाधीश {एस.एन.वरियावा और डॉ. एआर लक्ष्मणन, जे.जे.}, जो आईएफजीएल के मामले का फैसला करने वाली पीठ में शामिल थे, वही थे जिन्होंने मझगांव डॉक लिमिटेड के मामले में फैसला सुनाया था। एक और प्रासंगिक कारक जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि दोनों निर्णय एक पखवाड़े के थोड़े से अंतराल के भीतर दिए गए थे। मझगांव डॉक लिमिटेड में निर्णय 28 जुलाई, 2005 को दिया गया था जबकि आईएफजीएल के मामले में निर्णय 09 अगस्त,

2005 को दिया गया था। इस प्रकार, आईएफजीएल के मामले में फैसला सुनाते समय, वही बेंच मझगांव डॉक लिमिटेड में ठीक पहले दिए गए अपने फैसले के प्रति सचेत थी।

22. मझगांव डॉक लिमिटेड के मामले में फैसले को पढ़ने से पता चलेगा कि उक्त मामले में निर्धारिती को सरकार से 20% की सब्सिडी प्राप्त हुई थी, जिसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रयोजन के लिए लेनदेन मूल्य पर पहुंचने के लिए राजस्व द्वारा 'अतिरिक्त विचार' के रूप में शामिल करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने माना कि यह सब्सिडी खरीदार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं हुई थी और इसलिए, उत्पाद शुल्क के उद्देश्य से इसे माल की कीमत में शामिल नहीं किया जा सकता था। उस मामले के तथ्यों पर, न्यायालय ने पाया कि उक्त मामले में प्रतिवादी ने जैक-अप रिग्स के निर्माण और आपूर्ति के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के साथ अनुबंध किया था। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए सरकार की नीति के मुताबिक 20 फीसदी सरकार से और 10 फीसदी ओएनजीसी से सब्सिडी मिलनी थी। जहां तक ओएनजीसी से प्राप्त 10% सब्सिडी का सवाल है, इसे खरीदार से मिलने वाले अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में लेनदेन मूल्य में भी शामिल किया जाना था। हालाँकि, सरकार की ओर से 20% सब्सिडी सरकार की अपनी योजना के तहत थी, जिसमें ओएनजीसी (उक्त मामले में खरीदार) की कोई भूमिका नहीं थी। जाहिर है, यह नहीं कहा जा सकता कि इस सब्सिडी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ओएनजीसी से कोई प्रवाह था। इसलिए, उक्त निर्णय का वर्तमान मामले पर कोई प्रभाव नहीं है।

23. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि यह मामला पूरी तरह से /एफजीएल के 11 मामले में इस न्यायालय के फैसले से कवर होता है। इस प्रकार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द करते हैं और आयुक्त द्वारा पारित आदेश को बहाल करते हैं। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति है।

(यह अनुवाद एआई टूल: सुवास की सहायता से अनुवादक रुचिका गुलेच्छा द्वारा किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।